भारत सरकार

खान मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 859

दिनांक 07.02.2024 को उत्तर देने के लिए

महाराष्ट्र में डी.एम.एफ.

†859. श्री राजन बाबूराव विचारे:

क्या खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विगत तीन वर्षों के दौरान विकास कार्यों को करने के लिए, विशेषकर महाराष्ट्र के जनजातीय जिलों को जिला खनिज प्रतिष्ठान (डीएमएफ) से आवंटित निधियों का राज्य-वार मद-वार और स्थान-वार ब्यौरा क्या है; और

(ख) उक्त अवधि के दौरान डीएमएफ द्वारा जनजातीय जिलों विशेषकर महाराष्ट्र में खर्च की गई धनराशि से लाभान्वित हुए लोगों का वर्ष-वार ब्यौरा क्या है?

उत्तर

खान, कोयला एवं संसदीय कार्य मंत्री

(श्री प्रल्हाद जोशी)

(क) और (ख): वर्ष 2015 में खान और खनिज (विकास और विनियमन) (एमएमडीआर) अधिनियम में संशोधन के माध्यम से, भारत सरकार ने विशेष रूप से खनन प्रभावित क्षेत्रों में विकासात्मक और कल्याणकारी परियोजनाओं/कार्यक्रमों को शुरू करने के लिए खनन से प्रभावित सभी जिलों में जिला खनिज फाउंडेशन की स्थापना का प्रावधान किया है। वर्ष 2015 में, केंद्र सरकार ने प्रधान मंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजना (पीएमकेकेकेवाई) दिशा-निर्देश परिचालित किए और इसके अतिरिक्त दिनांक 15.01.2024 के आदेश के माध्यम से केंद्र सरकार ने पीएमकेकेकेवाई दिशानिर्देशों को संशोधित किया तथा इन्हें राज्य सरकारों को उनके द्वारा बनाए गए डीएमएफ नियमों में शामिल करने के निदेश दिए। ये दिशा-निर्देश विधिवत रूप से योजना के तहत कवर किए जाने वाले प्रभावित क्षेत्रों की पहचान निर्धारित करते हैं और उन प्रभावित क्षेत्रों जिनमें जनजातीय निवास-स्थानों को शामिल किया जा सकता है, की पहचान संबंधित डीएमएफ द्वारा राज्य सरकार द्वारा राज्य डीएमएफ नियमों में यथा निर्धारित तरीके से की जाती है।

पीएमकेकेकेवाई दिशा-निर्देश 2024 के अनुसार, कम से कम 70% निधियां पेयजल आपूर्ति, पर्यावरण संरक्षण और प्रदूषण नियंत्रण उपायों, स्वास्थ्य देखभाल, शिक्षा, महिला एवं बाल कल्याण, वृद्ध एवं दिव्यांगजन कल्याण, कौशल विकास और आजीविका सृजन, स्वच्छता, आवास, कृषि और पशुपालन जैसे उच्च प्राथमिकता वाले क्षेत्रों पर व्यय की जानी हैं। 30% तक निधियां वास्तविक अवसंरचना, सिंचाई,

ऊर्जा एवं वाटरशेड विकास जैसे अन्य प्राथमिकता वाले क्षेत्रों और खनन प्रभावित जिले में पर्यावरण की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए किसी अन्य उपायों पर व्यय की जानी हैं। दिसंबर 2023 तक, 87,049 करोड़ रुपये एकत्र किए गए हैं, 3,21,466 संस्वीकृत परियोजनाओं के लिए 80,322 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं और देश के 23 राज्यों में 644 डीएमएफ जिलों में 1,73,054 परियोजनाएं पूरी की गयी हैं।

महाराष्ट्र सरकार से प्राप्त सूचना के अनुसार, महाराष्ट्र राज्य में अधिकांश जनजातीय आबादी चंद्रपुर, गढ़चिरौली, गोंदिया, नागपुर, अमरावती, यावतमाल, धुले, नन्दुरबार, जलगांव, नासिक, पालघर और ठाणे जिलों में बसी हुई है। वित्त वर्ष 2020-21, वित्त वर्ष 2021-22 और वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान महाराष्ट्र के इन जनजातीय बहुल जिलों में डीएमएफ के तहत लाभार्थियों की संख्या क्रमशः 25359, 3882 और 9283 है। इन जिलों को डीएमएफ से आवंटित निधियों का ब्यौरा अनुबंध-I में दिया गया है। पिछले तीन वर्षों के दौरान निधि संग्रह और व्यय की गई राशि का ब्यौरा अनुबंध II में दिया गया है।

***

अतारांकित प्रश्न संख्या- 859 के भाग (क) और (ख) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध-I

निधि आवंटन (करोड़ रुपये में)	वित्त वर्ष 2020-21	वित्त वर्ष 2021-22	वित्त वर्ष 2022-23	वित्त वर्ष 2020-21	वित्त वर्ष 2021-22	वित्त वर्ष 2022-23	वित्त वर्ष 2020-21	वित्त वर्ष 2021-22	वित्त वर्ष 2022-23
क्षेत्र-वार कार्य	चंद्रपुर			गढ़चिरौली			गोंदिया		
शिक्षा, स्वास्थ्य एवं पेयजल जैसे उच्च प्राथमिकता वाले कार्य-60%	96.12	151.31	39.67	0.05	0.90	5.53	0.55	1.32	0.00
वास्तविक अवसंरचना, सिंचाई एवं पर्यावरण जैसे अन्य प्राथमिकता वाले कार्य-40%	61.65	115.46	0	0.03	0.00	4.93	0.06	0.91	0.38
कुल	157.77	266.77	39.67	0.08	0.90	10.46	0.61	2.23	0.38
क्षेत्र-वार कार्य	यावतमाल			धुले			नन्दुरबार		
शिक्षा, स्वास्थ्य एवं पेयजल जैसे उच्च प्राथमिकता वाले कार्य-60%	4.10	18.61	62.11	0.24	*	*	*	*	*
वास्तविक अवसंरचना, सिंचाई एवं पर्यावरण जैसे अन्य प्राथमिकता वाले कार्य-40%	0.00	2.47	38.95	0.01	0.01	0.01	0.04	0.19	0.00
कुल	4.10	21.08	101.06	0.25	0.01	0.01	0.04	0.19	0.00
क्षेत्र-वार कार्य	पालघर			ठाणे			अमरावती		
शिक्षा, स्वास्थ्य एवं पेयजल जैसे उच्च प्राथमिकता वाले कार्य-60%	0.00	0.00	0.48	3.71	0.00	1.18	2.12	0.88	0.60
वास्तविक अवसंरचना, सिंचाई एवं पर्यावरण जैसे अन्य प्राथमिकता वाले कार्य-40%	0.77	0.00	0.42	0.04	0.35	0.00	1.14	0.02	3.07
कुल	0.77	0.00	0.9	3.75	0.35	1.18	3.26	0.9	3.67
क्षेत्र-वार कार्य	नागपुर			जलगांव			नासिक		
शिक्षा, स्वास्थ्य एवं पेयजल जैसे उच्च प्राथमिकता वाले कार्य-	119.66	106.99	49.02	2.80	1.02	0.00	1.54	0.00	0.00

60%									
वास्तविक अवसंरचना, सिंचाई एवं पर्यावरण जैसे अन्य प्राथमिकता वाले कार्य-40%	77.93	69.61	71.10	0.72	0.17	0.19	0.77	0.00	0.56
कुल	197.59	176.60	120.12	3.52	1.19	0.19	2.31	0.00	0.56

*निधि संचयन कम होने के कारण इस प्राथमिकता वाले क्षेत्र के अंतर्गत कोई कार्य शुरू नहीं किया गया है।

अतारांकित प्रश्न संख्या-859 के भाग (क) और (ख) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध-II

पिछले तीन वर्षों के दौरान महाराष्ट्र के जनजातीय बहुल जिलों में डीएमएफ संग्रह और व्यय की गई राशि

क्र. सं.	जिला	कुल डीएमएफ संग्रह (करोड़ रुपये में)			व्यय की गई राशि (करोड़ रुपये में)		
		2020-21	2021-22	2022-23	2020-21	2021-22	2022-23
1	ठाणे	3.89	12.12	16.84	3.33	0.35	0.83
2	पालघर	3.86	6.90	13.94	0.54	0.21	0.53
3	नासिक	4.67	9.47	12.81	0.77	0.00	0.56
4	धुले	1.05	1.15	3.87	0.25	0.01	0.01
5	नन्दुरबार	0.20	4.96	2.47	0.00	0.19	0.00
6	जलगांव	4.26	7.01	0.00	1.82	1.29	0.18
7	अमरावती	5.31	5.08	8.38	9.56	0.75	2.16
8	यावतमाल	75.29	103.41	214.76	19.81	35.22	63.76
9	नागपुर	128.64	165.39	235.25	155.80	120.37	109.29
10	गोंदिया	1.79	2.31	4.35	0.53	2.23	0.38
11	चंद्रपुर	205.04	220.50	317.58	136.75	175.17	167.85
12	गढ़चिरौली	3.86	11.67	108.83	0.07	0.88	7.80
	कुल	437.86	549.97	939.08	329.23	336.67	353.35